देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 21.02.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- परिवहन सुधारों में उत्तराखण्ड को बड़ी उपलब्धि, केन्द्र से 125 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम ने आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों के संबंध में सभी ज़िलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
- प्रदेश में 'जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार' अभियान सम्पन्न। पांच लाख से अधिक लोगों ने भाग लेकर विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया।
- उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। दो लाख से अधिक छात्र–छात्राएं होंगे शामिल।

परिवहन धनराशि

उत्तराखण्ड में परिवहन क्षेत्र में किए जा रहे व्यापक सुधारों की केन्द्र सरकार ने सराहते हुए पूंजीगत निवेश योजना 2025–26 के अंतर्गत राज्य को 105 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। साथ ही अप्रैल से पूर्व लागू किए गए सुधारों के लिए 20 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि भी स्वीकृत की गई है। इस तरह 125 करोड़ की प्रोत्साहन राशि परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड को प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त यह प्रोत्साहन राशि, राज्य में स्मार्ट और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में परिवहन क्षेत्र में तकनीक आधारित सुधारों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ–साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट और वाहन स्क्रैपिंग नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम ने सचिवालय में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की तैयारियों के संबंध में सभी राज्य के सभी ज़िलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में उत्तराखण्ड में एसआईआर प्रस्तावित है, लेकिन देहरादून, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों में मतदाताओं की मैपिंग की प्रगति लक्ष्य के अनुरुप कम है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिन बूथों पर मैंपिग प्रतिशत कम है, वहां संबंधित ईआरओ और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी एसआईआर के कार्य में लापरवाही बरतेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों को तय समय सीमा में एसआईआर की तैयारियों के क्रम में बूथ जागरुकता समूह के गठन के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 77 प्रतिशत बूथों पर बूथ लेवल

एजेंट्स की तैनाती हो चुकी है। उन्होंने जिलाधिकारियों को बूथ लेवल एजेंट्स की शत–प्रतिशत तैनाती के लिए राजनैतिक दलों के साथ फिर से बैठक करने को कहा। बैठक में श्री पुरुषोत्तम ने एसआईआर हेल्प डेस्क के लिए जिलों में शीघ्र अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती किए जाने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा "इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट" जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर नाटकीय प्रदर्शन कर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास निंदनीय है और इससे कांग्रेस की राष्ट्रविरोधी सोच उजागर होती है। उन्होंने कहा कि भारत का विरोध कर देश के दुश्मनों का एजेंडा चलाने वाली कांग्रेस ने करोड़ों देशवासियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी, आर्थिक और सामरिक शक्ति को स्वीकार कर रहा है, तब इस प्रकार की राजनीति देशहित के विपरीत है।

देवरा यात्रा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रुद्रप्रयाग जिले में अगस्त्यमुनि विकासखंड के ग्राम बीरों देवल में आयोजित मां चंडिका महावन्याथ देवरा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने मां चंडिका मंदिर महायज्ञ में भाग लिया और पूजा–अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने आयोजन स्थल को धार्मिक और आध्यात्मिक संगम का प्रतीक बताते हुए कहा कि 20 वर्षों के बाद आयोजित यह महायज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा ऐसे आयोजन न केवल समाज में समरसता और एकता को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं और मूल जड़ों से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां चंडिका मंदिर प्रांगण और मंदिर समूह का पुरातत्व विभाग के माध्यम से पुनर्निर्माण कराये जाने तथा तहसील बसुकेदार में नवीन तहसील भवन निर्माण की घोषणा की।

जन–जन की सरकार

प्रदेश में 65 दिनों तक चलाया गया 'जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार' अभियान कल सम्पन्न हो गया। 17 दिसम्बर से शुरू हुए इस अभियान के दौरान प्रदेशभर में 681 शिविर लगाए गए, जिनमें 5 लाख 33 हजार 452 नागरिकों ने प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेकर विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया। साथ ही अपनी समस्याएं भी दर्ज कराई।

प्रदेश में 'जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार' अभियान के तहत आयोजित शिविरों में 51 हजार से अधिक शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 33 हजार 755 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्रों के लिए 74 हजार 184 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर त्वरित गति से कार्य किया जा रहा है। वहीं, करीब तीन लाख लोगों ने विभिन्न सेवाओं का भी लाभ लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से लोगों को बिना किसी भागदौड़ के सरकारी सेवाओं का लाभ मिला है और यही सुशासन की पहली सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि

प्रदेश सरकार योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि यह विशेष अभियान भले ही सम्पन्न हो गया हो, लेकिन प्रशासन लगातार जनता के सम्पर्क में बना रहेगा। अधिकारियों को भविष्य में भी जन शिकायतों का त्वरित समाधान करने को कहा गया है।

बोर्ड परीक्षा

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। प्रदेशभर में एक हजार 261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 156 संवेदनशील और छह अति संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इस वर्ष दो लाख से अधिक छात्र–छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि परीक्षाओं को नकलविहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभागीय अधिकारियों, जिला प्रशासन और पुलिस को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित आपूर्ति और गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। डॉ. रावत ने ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे बिना तनाव के आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। अभिभावकों और शिक्षकों से भी परीक्षा के दौरान बच्चों का मनोबल बढ़ाने की अपील की गई है।

खाद्य सुरक्षा अभियान

खाद्य सुरक्षा विभाग ने बागेश्वर नगर क्षेत्र स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया। होली पर्व के दृष्टिगत विशेष रूप से ऐसे वितरक और आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जो बाहरी जिलों से खाद्य सामग्री मंगाकर स्थानीय विक्रेताओं को आपूर्ति करते हैं। इस दौरान टीम ने दूध और दाल के सैम्पल लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि वे खाद्य सामग्री केवल पक्के बिल और परिवहन प्रपत्र के साथ ही मंगाएं तथा एक्सपायर्ड या वापसी योग्य सामग्री का अलग से रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि होली पर्व के दौरान जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर–

शीर्षस्थ अमेरिकी कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध घोषित करने की ख़बर आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। अमर उजाला लिखता है– सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ किया निरस्त, ट्रंप ने थोपा दस प्रतिशत अस्थायी शुल्क, भारत पर अब 18 की बजाय दस फीसदी होगा टैरिफ।

देहरादून ज़िले के राशन कार्ड धारकों को इस माह राशन के लिये थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हिंदुस्तान समाचार पत्र के अनुसार राशन उठान का कार्य अगले सप्ताह से शुरू होगा, जो मार्च के पहले सप्ताह में बंटना शुरू होगा।

ड्रैगन फ्रूट, कीवी और सेब बागवानी योजना से राज्य बनेगा फल पट्टी। इस शीर्षक के साथ अमर उजाला लिखता है– मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने उत्तराखंड को फल पट्टी बनाने के लिये दस कलस्टरों का चरणबद्ध तरीके से विकास करने के निर्देश दिए हैं।

ऋषिकेश में एक हजार एक सौ बावन करोड़ रुपए की लोगत से बनेगा बाईपास हाईवे, हिंदुस्तान समाचार पत्र की सुर्खी है। समाचार पत्र के अनुसार तीनपान से ढालवाला होते हुए खाराश्रोत तक नए हाईवे की डीपीआर तैयार कर भेज दी गई है। अगले सप्ताह तक ये डीपीआर भारत सरकार को भेज दी जाएगी।